अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को सीमेंट लाइसेंस जारी किया जाना

2075. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान खाद्य और नागरिक पूर्ति आयुक्त, दिल्ली प्रशासन ने अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को दस हजार रुपए की धरोहर राशि के एवज में सीमेंट के लाइसेंस जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "हां" हो तो क्या यह भी सच है कि खाद्य और नागरिक पूर्ति आयुक्त ने उक्त लाइसेंस मुख्य सचिव या उप-राज्यपाल से बिना कोई अनुमति प्राप्त किए जारी किए हैं ; और

(घ) क्या सरकार इस संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने का विचार रखती है ; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) लाइसेंसधारियों से जमानत की राशि, दिल्ली सीमेंट (लाइसेंसिंग एण्ड कंट्रोल) आर्डर, 1972 के उपबंधों के अनुसार, लाइसेंस की श्रेणी के आधार पर ली जाती है। लाइसेंसों की दो श्रेणियां है, पहली वितरक का कार्य करने के लिए और दूसरी विक्रय एजेंसी के लिए। वितरक का कार्य करने के लिए जमानत की राशि 10,000 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि स्टॉकिस्ट/विक्रय एजेंट के लिए यह राशि 5000/–रुपये निर्धारित की गई है। तथापि, यदि लाइसेंसधारी एक सहकारी समिति, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य, बेरोजगार स्नातक, भूतपूर्व सैनिक अथवा विकलांग व्यक्ति हो तो उस मामले में उक्त जमानत राशि को घटाकर आधा कर दिया जाता है। बहुसंख्यक अथवा अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करने के लिए जमानत राशि के संबंध में कोई भेद नहीं किया जाता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नक्शों के आधार पर सीमेंट का आवंटन

2076. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ असामाजिक तत्व दिल्ली प्रशासन के खाद्य और नागरिक पूर्ति मुख्यालय में उपयुक्त प्राधिकारियों से सांठ-गांठ करके नक्शों के आधार पर नए मकानों या इमारतों के निर्माण के लिए सीमेंट प्राप्त करते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार किसी खुफिया एजेन्सी से उन सभी नक्शों का सत्यापन कराने का विचार रखती है जिससे कि नक्शों की प्रमाणिकता का पता लगाया जा सके ; यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) दिल्ली प्रशासन ने इस बात से इंकार किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में कालोनियों को नियमित किया जाना

2877. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की ऐसी कालोनियों के नाम तथा पते क्या हैं जो पिछले

20 वर्ष से हैं किन्तु जिन्हें अब तक नियमित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या सरकार इस प्रकार की कालोनियों को नियमित किए जाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस प्रकार की कालोनियों के नियमितीकरण की नीति के अनुसार नियमितीकरण के लिए विचारार्थ 1977–78 में दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम द्वारा संकलित की गई 607 अनधिकृत कालोनियों की सूची में से 56 कालोनियों को अस्वीकार कर दिया गया है, 7 को अधिसूचित मलिन बस्तियों को हस्तांतरित कर दिया गया है तथा शेष 4 कालोनियों के मामलों पर अभी भी निर्णय लिया जाना है। इन 67 कालोनियों की सूची संलग्न है। [देखिए परिशिष्ट CXLIV अनुबंध सं० 90]

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Reasons for non-commissioning of Haldia Fertilizer Plant

2078. SHRI MOSTAFA BIN QUASEM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether mis-matching of equipments or techno-managerial lapse were responsible for the present state of affairs of the Haldia plant of HFC;

(b) what steps Government propose to take against the erring top officials attached with the plant who have squandered away crores of rupees at the cost of the plant; and

(c) what steps Government are planning to take for the commissioning of the plant?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) Mis-match of equipment arising mainly from multiple credits and major indigenisation of equipment of mainly responsible for the non-commissioning of the Haldia plant of Hindustan Fertilizer Corporation Limited.

(b) Does not arise.

(c) Government has decided to undertake an end to end survey of the project, for which consultants are being engaged.

Vegetable scandal unearthed in the Super Bazar, Delhi

2079. SHRI R. SAMBASIVA RAO:
SHRI J. P. GOYAL:
SHRI RAMNARAYAN GOSWAMI:
SHRI RAJNI RANJAN SAHU:

Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that recently a multi-million rupee vegetable scandal had been unearthed in the Super Bazar in Delhi;

(b) whether it is also a fact that the residents of Delhi have not only been supplied sub-standard vegetable by the Super Bazar but have also been made to pay more for it; and

(c) if so, what action Government propose to take to streamline the functioning of the Super Bazar and to ensure that the general public are not cheated by the Super Bazar by sub-standard vegetable to them at exorbitant prices?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUP-